श्री तपन कुमार सेन (पश्चिमी बंगाल): सर, पूरा करने दीजिए। अभी एक मिटन बाकी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप क्या कह रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, please don't ring the bell. ...*(Interruptions)*...

SHRI MOHAMMED AMIN: Sir, they want reversal of policies which exclude millions of people from the protection of their rights and livelihood by the governance.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over. ...*(Interruptions)*... Please.

SHRI MOHAMMED AMIN: Only a fortnight before, on 23rd February, lakhs of workers demonstrated before Parliament. Therefore, I urge upon the Government to please take the call before it is delayed too much.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MANGALA KISAN (Orissa): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I also associate myself with this important issue.

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

SPECIAL MENTIONS

Need to make the appointment process of Directors and CMDs of Public Sector undertakings transparent

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभापति महोदय, देश की अर्थनीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अभी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग अभी भी यह चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां लाभ देती हैं, वे सब कार्यक्षम रहें, लेकिन कभी-कभी यह महसूस होता है कि वैश्वीकरण के कारण भारत के इन महान संगठनों पर काले बादल मंडरा रहे हैं। निजी अर्थनीति के समर्थक ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे कि पब्लिक सेक्टर

के उपक्रम नुकसानग्रस्त हो जाएं और धीरे-धीरे बंद हो जाएं। इन संगठनों में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (Chairman-cum-Managing Director) और तमाम निदेशक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इन पदों पर अत्यधिक पारदर्शी व्यक्ति नियुक्त हों, ऐसा सरकार को देखना चाहिए। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के तमाम निदेशक पदों पर एवं सी.एम.डी. के पद पर नियुक्ति के समय कार्मिक मंत्रालयाधीन "पी.ई.एस.बी." (Public Enterprises Selection Board) और डी.ओ.पी.टी. (Department of Personnel and Training) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चयनित होने वाले अधिकारियों की पृष्ठभूमि का अत्यंत बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रक्रिया का पारदर्शी होना भी अत्यंत आवश्यक है। अब देश भर में यह वातावरण है कि इन पदों पर नियुक्ति के समय पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। हाल में नाल्को के सी.एम.डी. को लेकर जो समाचार आ रहा है, इससे यह भावना द्विगुणित हो रही है। National Aluminium Company जैसी नवरत्न कंपनी के सी.एम.डी के पद पर नियुक्ति के समय और अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए थी - ऐसा विचार लोगों में अब आ रहा है, जो कि अत्यंत स्वभाविक है। अब तो ऐसा रहस्योद्घटन हो रहा है जिससे कि इस पदवी की चयन प्रक्रिया और चयनकारी संस्थाओं के प्रति भी लोगों के मन में संदेह जाग्रत हो रहा है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि नाल्को जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के तमाम निदेशक तथा सी.एम.डी. पदों के चयन के समय अधिक गंभीरता से ध्यान दिया जाए एवं और अधिक पारदर्शिता अपनाई जाए।

Need for establishment of Aviation University in Hyderabad

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Andhra Pradesh): Sir, after opening up of Shamshabad Airport, Begumpet Airport has become inoperative. So, the Government of Andhra Pradesh thought to utilize land available optimally and proposed to set up an Aviation University with the help of the Airports Authority of India in 300 acres out of 800 acres of land and the BCAS also accepted this proposal. The objective is to provide aviation training, flying, management, safety, security, etc. Apart from Aviation University, the Airports Authority of India also wanted to set up AATI to offer technical courses and other related training in communication, navigation systems and ATM. The proposal has also sent to the HRD Ministry which is also positive on this project.

When the Chief Minister had written a letter to the Prime Minister on August 27, 2010, it was sent to the Civil Aviation Ministry for examination and feasibility. Since the Airports Authority of India - main wing of the Aviation Ministry - has already agreed for setting up of an Aviation University, the Andhra Pradesh Government thought that the project would come up soon. But, the Cabinet Secretary in November last had rejected the proposal and asked the State Government to provide alternative site of 400 acres for University. I understand that the Cabinet Secretary wants to use this